



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2016/भाद्र 11, 1938

No. 289]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2016/BHADRA 11, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2016

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

विषय : सऊदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “नार्मल बुटानोल” और “एन-बुटाइल अल्कोहल” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क संबंधी जांच की शुरूआत।

Qk सं- 14/20/2016.—डीजीएडी: मै. दि आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे ‘याचिकाकर्ता’ या ‘आवेदक’ कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा (क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार सऊदी अरब (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नार्मल बुटानोल (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या ‘एनबीए’ भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क संबंधी जांच की शुरूआत के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष संगत सूचना के साथ एक आवेदन (जिसे याचिका भी कहा गया है) प्रस्तुत की है।

- और यतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की

मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

घरेलू उद्योग और आधार

3. यह आवेदन मै. दि आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता देश में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारत में उत्पादित समान उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन बनता है। यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता न तो संबद्ध वस्तु का आयात करता है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित नहीं है। इस प्रकार यह निर्धारित किया जाता है कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अधीन 'योग्यता' संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसके अलावा, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान याचिका और प्रस्तावित जांच में विचाराधीन उत्पाद 'नार्मल ब्युटानोल' है। नार्मल ब्युटानोल एक मूल कार्बनिक रसायन है जिसे आम तौर पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। नार्मल ब्युटानोल 4-कार्बन संरचना और अणु सूत्र $CH_3CH_2CH_2CH_3$ वाला एक प्राथमिक अल्कोहल है। नार्मल ब्युटानोल यूरिया, मेलामाइन या फेनोलिक रेजिंस से उत्पन्न एसिड-क्यूरेबल लेकर्स और बेकिंग फिनिशेस के लिए एक उत्कृष्ट विलायक है। एन-ब्युटानोल के एक बड़े हिस्से को कोटिंग उद्योगों में विलायक के रूप में प्रयोग हेतु व्युत्पत्तियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 29051300 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जात है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

5. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में संबद्ध देश से निर्यात की गई संबद्ध वस्तु, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की गई वस्तु के समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित नार्मल ब्युटानोल भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के अनुसार तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

शामिल देश

6. वर्तमान जांच में शामिल देश सऊदी अरब है।

सामान्य मूल्य

7. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमत की सूचना/साक्ष्य जुटाने के प्रयास किए गए थे। तथापि याचिकाकर्ता यह सूचना नहीं प्राप्त कर पाया। अतः याचिकाकर्ता ने प्रमुख कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, घरेलू उद्योग के सर्वोत्तम खपत मानक, घरेलू उद्योग और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के अनुसार परिवर्तन और अन्य लागत पर विचार करते हुए संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य को परिकलित किया है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के दावे की जांच की है और नोट किया जाता है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

निर्यात कीमत

8. आवेदक ने भारत में आयातों की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए डीजीसीआईएंड एस के सौदा-वार आकड़ों पर आधारित विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्यात कीमत का दावा किया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन और प्रहस्तन व्यय के लिए कीमत संबंधी समायोजन किये गये हैं।

पाटन मार्जिन

9. आवेदक ने इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराये हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य संगत निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु को पाटित किया जा रहा है जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत न्यायोचित सिद्ध करता है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

10. आवेदक ने दावा किया है कि पाटित आयातों से उसे वास्तविक क्षति हुई है और उसने समग्र रूप से आयातों में वृद्धि, उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग में कमी, लाभों, नियोजित पूंजी पर आय, नकद लाभ आदि में कमी के अनुसार संबद्ध देश से कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने कीमत कमी और कीमत कटौती/कम कीमत पर बिक्री के साक्ष्य के रूप में प्रतिकूल कीमत प्रभावों का भी दावा किया है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा आवेदक को हो रही क्षति के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

जांच अवधि

11. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1.4.2015 से 31.3.2016 तक मानी गई है। इसके अलावा, क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2012- मार्च 2013, अप्रैल 2013- मार्च 2014, अप्रैल 2014- मार्च 2015 और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच से संगत अनुरोध कर सकता है और सूचना निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत की जा सकती है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

समय-सीमा

13. इस जांच च से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. सभी हितबद्ध पक्षकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार प्रदत्त गोपनीय सूचना के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय और अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराएंगे।

15. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध 'गोपनीय' होने का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

16. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

17. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

18. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

19. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

20. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

New Delhi, the 2nd September, 2016

INITIATION NOTIFICATION

Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of “Normal Butanol” or “N-BUTYL ALCOHOL” originating in or exported from Saudi Arabia.

F. No.14/20/2016 – DGAD.—M/s The Andhra Petrochemicals Limited, (hereinafter referred to as ‘petitioner’ or ‘the applicant’) has filed an application (also referred to as petition) along with relevant information before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Normal Butanol (hereinafter referred to as the subject goods or “NBA”) originating in or exported from Saudi Arabia (hereinafter also referred to as the subject country).

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the dumping and ‘injury’ exists to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The application has been filed by M/s The Andhra Petrochemicals Limited. The petitioner is the sole producer of the subject goods in the country. It is also noted that the production by the petitioner constitutes total Indian production of the like product produced in India. It is also noted that petitioner has neither imported the subject goods, nor are they related to an importer or exporter of the subject goods. It is, thus, determined that the application has been made by and on behalf of the domestic industry and the application satisfies the requirements of ‘standing’ under Rule 5 of the AD Rules. Further, the Applicant constitutes ‘Domestic Industry’ in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

Product under consideration

4. The product under consideration in the present petition and proposed investigation is “Normal Butanol”. Normal Butanol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. Normal Butanol is a primary alcohol with a 4-carbon structure and molecular formula C₄H₉OH. Normal Butanol is an excellent solvent for acid-curable lacquers and baking finishes derived from urea, melamine or phenolic resins. A large part of Normal Butanol is converted into derivatives for use as solvents in coating industries. This product is classified under Customs Tariff heading No. 29051300. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

5. The applicant has claimed that the subject goods, which are exported from subject country into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. Normal Butanol produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the

goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence, should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Subject Countries

6. The country involved in the present investigation is Saudi Arabia.

Normal value

7. The Petitioner has submitted that efforts were made to get information/evidence of price of subject goods in the domestic market of the subject country. However, petitioner was not able to get such information. The petitioner has, therefore, constructed normal value for the subject country taking into account the international price of major raw materials, best consumption norm of domestic industry, conversion and other cost as per domestic industry and reasonable profit margin. The Authority has examined the claim of the petitioner and notes that there is sufficient prima facie evidence of normal value of the subject goods in the subject country.

Export price

8. The applicant has claimed export price for product under consideration based on DGCI&S transaction-wise data to assess the volume and value of imports into India. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port and handling expenses.

Dumping Margin

9. The applicant has provided sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are significantly higher than the corresponding net export price, prima-facie indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being dumped, to justify initiation of the antidumping investigation.

Injury and Causal Link

10. The applicant has claimed that they have suffered material injury and have furnished evidence regarding injury having taken place as a result of the alleged dumping from subject country in terms of increase in imports in absolute terms, decline in production, sales, capacity utilization, deterioration in profits, return on capital employed, cash profit etc. The applicant has also claimed adverse price effects as evidenced by price suppression and price undercutting/underselling. The Authority considers that there is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the applicant caused by dumped imports of subject goods from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation

11. The period of investigation for the present investigation has been considered as 1.4.2015 to 31.3.2016. Further the injury investigation period will cover the periods April 2012 to March 2013, April 2013 to March 2014, April 2014 to March 2015 and the Period of Investigation (POI).

Submission of information

12. The known exporters in the subject country and their Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file relevant information in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street
New Delhi-110001

Time limit

13. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

Submission of information on confidential basis

14. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7(2) of the AD Rules for the confidential information provided as per Rule 7(1) of the AD Rules.

15. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page.

16. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

17. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

18. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

19. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

Inspection of Public File

21. In terms of rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

22. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority